

# बंगाल में पानी के नीचे मेट्रो शुरू

## प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, पहली बार हुगली नदी के नीचे सुरंग के जरिये गुजरी कोलकाता मेट्रो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता मेट्रो के एस्पलेनैड-हावड़ा मैदान खंड का उद्घाटन किया। यह खंड देश में पहली बार पानी के अंदर बनी परिवहन सुरंग के माध्यम से हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरता है। मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं।

अधिकारियों ने बताया कि 4.8 किलोमीटर लंबा हावड़ा मैदान-एस्पलेनैड खंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और इसका निर्माण 4,960 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जोका-एस्पलेनैड लाइन के 1.25 किलोमीटर तारातला-माजरहाट खंड का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण 520 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। एस्पलेनैड मेट्रो स्टेशन पर समारोह स्थल से प्रधानमंत्री ने न्यू गिरिया-एयरपोर्ट लाइन के कवि सुभाष-हेमंत मुखोपाध्याय खंड का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण 1,430 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कवि सुभाष-हेमंत मुखोपाध्याय खंड 5.4 किलोमीटर लंबा है और इससे कोलकाता के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के इलाके मेट्रो के मानचित्र पर आ जाएंगे।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान-एस्पलेनैड खंड में 'भारत की किसी भी बड़ी नदी' के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी तट पर कोलकाता और हावड़ा स्थित हैं। इस खंड में हुगली नदी के नीचे हावड़ा मेट्रो स्टेशन है जो देश का सबसे गहराई में स्थित स्टेशन है।

कोलकाता से ही प्रधानमंत्री ने केरल के कोच्चि मेट्रो के 1बी पूर्ण चरण का बुधवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया और इसी के साथ ही एरणाकुलम जिले के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के लोगों को तटीय शहर तक तेज और आसान पहुंच प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री ने त्रिपुनिथुरा टर्मिनल मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से ही वर्चुअल माध्यम से दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे दुहाई-मोदीनगर उत्तर खंड



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में स्कूली छात्र-छात्राओं से बात की फोटो-पीटीआई

## आरआरटीएस और आगरा मेट्रो को भी हरी झंडी

- हावड़ा मैदान-एस्पलेनैड खंड पर नदी के नीचे पूरे देश में सबसे अधिक गहराई में बना है हावड़ा मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का 17 किमी दुहाई-मोदीनगर उत्तर खंड भी हुआ चालू
- आगरा मेट्रो को भी कोलकाता से वर्चुअल हरी झंडी दिखाई, मेट्रो स्टेशन के अंदर एआई से निगरानी

## सीबीआई की हिरासत में शाहजहां शेख

कलकत्ता उच्च न्यायालय से बुधवार सुबह नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत अंततः बुधवार शाम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। सीबीआई अधिकारियों की टीम अपराहन चाय बजे से पहले ही भवानी भवन पहुंच गई। लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी के हवाले शाम छह बजकर 48 मिनट पर किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने अब तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है।

का भी उद्घाटन किया। इसके चालू होने के साथ ही साहिबाबाद से मोदीनगर उत्तर तक 34 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन की सेवा आठ स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। इस अतिरिक्त खंड के उद्घाटन से तीन और स्टेशन मुराद नगर, मोदी नगर दक्षिण और मोदी नगर उत्तर शामिल हो गए हैं।

मोदी ने आगरा मेट्रो को भी कोलकाता से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई। इस मेट्रो लाइन के भूमिगत खंड का निर्माण 32 महीने में प्रस्तावित था, लेकिन यह 23 महीने में बनकर तैयार हो गया। सात दिसंबर, 2020

का प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया था। एक बयान के मुताबिक इस मौके पर ताज महल मेट्रो स्टेशन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर नवाना किया। मेट्रो स्टेशन के अंदर एआई से निगरानी की जाएगी। आगरा मेट्रो उम्र की छठी मेट्रो सेवा होगी। आगरा मेट्रो के शुरु होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसके पास सबसे अधिक शहर में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा प्रारंभ हो चुकी है।

भाषा

# भारतीय कंपनियों में औसतन 9.6 % वेतन वृद्धि की उम्मीद

राघव अग्रवाल

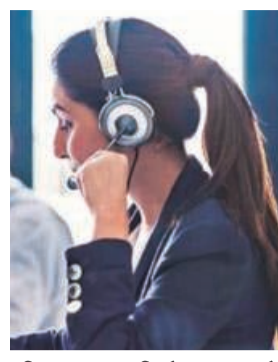
अनर्द एंड यंग (ईवाई) की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में भारतीय कंपनियों के कर्मचारियों की औसतन 9.6 फीसदी वेतन वृद्धि की उम्मीद है। यह पिछले साल यानी 2023 जितना ही है, मगर यह साल 2022 के 10.4 फीसदी से कम रहेगा।

प्यूचर ऑफ पे 2024 रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि ई-कॉमर्स कंपनियों के कर्मचारियों की होने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन 10.9 फीसदी तक बढ़ सकता है। वित्तीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन 10.1 फीसदी और पेशेवर सेवाओं तथा रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों की तनखाह 10-10 फीसदी बढ़ सकती है। साल 2023 में भी ई-कॉमर्स कंपनियों में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि हुई थी। वाहन, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन 10.4 फीसदी बढ़ा था।

रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि साल 2022 की तुलना में वेतन वृद्धि कम होने का मुख्य कारण ई-कॉमर्स क्षेत्र और प्रौद्योगिकी उप क्षेत्रों में अनुमानित गिरावट है। उसमें कहा गया है, 'साल 2022 में क्लाउड प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी जैसे कुछ प्रौद्योगिकी उप क्षेत्रों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी। मगर साल 2024 तक साल में गिरावट का अनुमान है।' ई-कॉमर्स क्षेत्र में आई गिरावट के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक महामारी से जुड़े बदलाव और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा बढ़ने को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है।

## वेरिबल पे फीसदी में गिरावट की आशंका

साल 2023 में भारत में कुल निश्चित वेतन के हिस्से के रूप में औसत वेरिबल पे 15.05 फीसदी था। मगर रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि किसी भी संगठन में जब व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो उसके वेरिबल पे का अनुपात भी बढ़ता है। पिछले साल व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के वेतन का 9.2 फीसदी और प्रबंधन स्तरीय अधिकारियों के वेतन का 10.7 फीसदी वेरिबल पे के रूप में दिया गया था। विभाग प्रमुख और



## ई-कॉमर्स में सबसे अधिक की उम्मीद

## ■ ईवाई की रिपोर्ट से खुलासा, इस साल औसतन 9.6 फीसदी बढ़ेगा वेतन

## ■ सबसे ज्यादा 10.9 फीसदी ई-कॉमर्स कंपनियों के कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

## ■ वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों की 10.1 फीसदी और पेशेवर सेवाओं पर रियल एस्टेट के कर्मचारियों की 10-10 फीसदी बढ़ सकती है तनखाह

वरिष्ठ अधिकारियों (सीएक्सओ) के लिए यह क्रमशः 14.1 फीसदी और 26.2 फीसदी से अधिक था।

साल 2024 में छोटे स्तर के कर्मचारियों को छोड़कर सभी स्तरों पर वेरिबल पे फीसदी कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'अधिकारियों को आम तौर पर अधिक वेरिबल पे मिलता है, लेकिन साल 2024 में उनकी अनुमानित वेतन वृद्धि साल 2023 से कम है।'

## नौकरी छोड़ने की दर वैश्विक महामारी पूर्व स्तर पर आई

ईवाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नौकरी छोड़ने की दर साल 2022 के 21.2 फीसदी से घटकर साल 2023 में 18.3 फीसदी हो गई। यह वैश्विक महामारी से पहले वाले स्तर पर आ गया है। अलग-अलग सर्वेक्षण में बताया गया है कि वैश्विक महामारी से पहले के साल में नौकरी छोड़ने की दर का स्तर 16 से 18 फीसदी के बीच था। इन 18.3 फीसदी में से 15.2 फीसदी लोग खुद से नौकरी छोड़ने वालों में थे और 4.2 फीसदी ने अनिच्छा से नौकरी छोड़ी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले साल की तुलना में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। यह 43 फीसदी से घटकर 34 फीसदी हो गया है।' साथ ही यह भी कहा गया है कि यह ऐतिहासिक मानदंडों से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा 13.2 फीसदी प्रबंधक स्तर के लोगों ने नौकरी छोड़ी। उसके बाद 10.5 फीसदी व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं और 9.9 फीसदी कार्य प्रमुखों ने अपनी नौकरी छोड़ी। अधिकारियों के बीच नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम नौ फीसदी रही।

भारत में खुद से नौकरी छोड़ने वालों के तीन सबसे बड़े कारण वेतन असमानता, सीखने और बढ़ने के सीमित अवसर और प्रदर्शन मूल्यांकन थे। क्षेत्र के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा (24.2 फीसदी) पेशेवर सेवाओं में कार्यरत लोगों ने नौकरी छोड़ी। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी (23.3 फीसदी) कंपनियों के कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'प्रतिभा की बेहतर उपलब्धता के कारण नौकरी छोड़ने की दर में कमी आने के संकेत मिले हैं।'

प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी जैसे कुछ प्रौद्योगिकी उप क्षेत्रों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी। मगर साल 2024 तक साल में गिरावट का अनुमान है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में आई गिरावट के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक महामारी से जुड़े बदलाव और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा बढ़ने को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है।

## वेरिबल पे फीसदी में गिरावट की आशंका

साल 2023 में भारत में कुल निश्चित वेतन के हिस्से के रूप में औसत वेरिबल पे 15.05 फीसदी था। मगर रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि किसी भी संगठन में जब व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो उसके वेरिबल पे का अनुपात भी बढ़ता है। पिछले साल व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के वेतन का 9.2 फीसदी और प्रबंधन स्तरीय अधिकारियों के वेतन का 10.7 फीसदी वेरिबल पे के रूप में दिया गया था। विभाग प्रमुख और

# बिहार को 12,800 करोड़ कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन आज रुपये की योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के पश्चिमी चंपारण में 12,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने रेल, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित कई आधारभूत परियोजनाओं को देश को समर्पित किया और कई का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में आधुनिक रेल इंजन विनिर्माण फैक्टरियों की शुरुआत उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई है। जिनकी भी रेल लाइन बिछाई जा रही हैं और जिनकी ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, वे सभी भारत में बन रही हैं। उन्होंने 109 किमी इंडियन ऑयल को मुजफ्फरपुर-मोतीहारी एलपीजी पाइपलाइन, इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पूरब और पश्चिम चंपारण में सिटी गैस वितरण परियोजना समेत

## मोदी ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित कई आधारभूत परियोजनाओं को देश को समर्पित किया

कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई का उद्घाटन भी किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनका परिवार 'बिहार का सबसे बड़ा गुनहगर' है। प्रधानमंत्री ने उन पर एक दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान राज्य में जंगल राज कायम करने का आरोप लगाया। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक रेले की संबंधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि राजद-कांग्रेस गठबंधन के कुशासन के परिणामस्वरूप बिहार के युवा बड़ी संख्या में पलायन करने के लिए मजबूर हुए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में चीजें बेहतर दिखने लगीं।

भाषा

# कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन आज

लोक सभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की गुरुवार को बैठक होगी। इस बैठक में ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। पार्टी महासचिव जयरांम रमेश ने कहा कि सीईसी की बैठक 7 मार्च को शाम छह बजे होगी। इसमें लोक सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सीईसी की बैठक में विभिन्न स्क्रूनिंग कमेटी द्वारा भेजे नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों के लिए स्क्रूनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है।

सूत्रों का कहना है कि सीईसी की बैठक में करीब 100 लोक सभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार होगा और प्रत्याशियों की पहली सूची कुछ दिनों के भीतर जारी हो सकती है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा था कि सात नामों को सीईसी की बैठक के बाद लोक सभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा होने की उम्मीद है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व



## ■ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार शाम को होगी बैठक, लोक सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर

अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के अलावा समिति में शामिल अन्य नेता बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

इस बीच, अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी

2024 का लोक सभा चुनाव अमेठी से लड़ेगा। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, जिसकी घोषणा शीघ्र ही जाएगी। सिंघल ने बताया कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, कार्यकर्ता अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी 2002 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे। वह 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेता स्पृति इरानी से चुनाव हार गये थे। राहुल इस समय केरल के वायनाड से सांसद हैं।

वहीं, निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए 'पनीनी' और 'जेबकतार' संबंधी बयानों के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने को कहा है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्वार्ड करते हुए आयोग ने गांधी को कहा कि वह स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए जारी हालिया परामर्श का सही तरीके से पालन करें।

भाषा

# किसानों के मार्च ऐलान पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, जाम

किसानों के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर बुधवार को यातायात प्रभावित हुआ। किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे दो प्रमुख संगठन किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (वैर-राजनीतिक) ने रविवार को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 10 मार्च को चार घंटे के देशव्यापी रैल रोकें। आंदोलन का भी आह्वान किया है।

किसानों के कूच की आशंका के चलते पुलिस चौकन्नी हो गई और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को दिल्ली-हरियाणा के सिंधु बॉर्डर और दिल्ली-नोएडा सीमा पर तैनात किया गया। इससे यहां वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं पुलिस से सीमाओं और शहर के अन्य हिस्सों में अवरोधक लगा दिए हैं और मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों पर जांच तेज कर दी। दिल्ली पुलिस



## दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा कड़ी

के मुताबिक, पुलिस बल टिकरी, सिंधु और गाजीपुर सीमाओं के साथ-साथ रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखेगा। एक अधिकारी ने बताया, 'हमने तीनों सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि हमने कोई सीमा या मार्ग को बंद नहीं किया है, लेकिन वाहनों की जांच की जाएगी।' किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार को दावा किया कि केंद्र ने किसानों को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती कर स्वीकार कर लिया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी है।

भाषा

# इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों का रुख कर रहे चालक

नितिन कुमार

दिल्ली में तीन पहिया वाहन चलाने वाले राजेश एम एक अच्छी वजह से बदलाव चाह रहे हैं और कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त हैं। यात्रियों की तलाश की बजाय वह एक नई गाड़ी खरीदने की योजना में बनाने में लगे हैं, मगर इस बार उनकी पसंद इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन खरीदने की है।

हाल ही में राजेश के दोस्तों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और उन्होंने बताया कि इससे ईंधन खर्च में बचत हो रही है। राजेश कहते हैं, 'वे सिर्फ ईंधन खर्च कम करते हैं, वे मेरे वजह से ही मुझे अधिक कमा रहे हैं।' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन पहिया वाहन चालक ईंधन के लिए हर दिन औसतन 450 रुपये कंसेट्रुड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर खर्च करते हैं। वहीं दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक वाहन चालक महज 200 रुपये खर्च करते हैं। अधिकतर इलेक्ट्रिक वाहन चालक अपने घर में या फिर चार्जिंग सुविधा

वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अपने वाहन चार्ज करते हैं। कुछ का यह भी कहना है कि वे स्कूल, मॉल और बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अपने वाहन चार्ज करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में अब तक देश भर में बेचे गए कुल 9,86,797 तीन पहिया वाहनों में 54 फीसदी इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां हैं। वित्त वर्ष 2015 में इसकी हिस्सेदारी महज 15 फीसदी थी। हालांकि, सीएनजी वाले तीन पहिया वाहनों में भी लगातार बिक्री देखी जा रही है। यह वित्त वर्ष 2019 के 1,98,616 इकाइयों से 53 फीसदी बढ़कर अभी 3,03,817 इकाइयों पर पहुंच गई है। मगर, सभी हरित ईंधन को एक जैसी सफलता नहीं मिली है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से चलने वाले वाहनों में काफी गिरावट देखी गई। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से कड़ी टक्कर मिलने के कारण



इसकी संख्या वित्त वर्ष 2019 के 1,03,950 इकाइयों से घटकर फिलहाल 25,442 हो गई है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की बिक्री को बल मिलने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रिक परिवहन पर सरकार के जोर देने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि से भी लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख किया है। राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्य अब डीजल वाहनों पर रोक के साथ सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर दे रहे हैं। मगर, इलेक्ट्रिक

तीन पहिया वाहनों की वृद्धि का एक अन्य कारण भी है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, उनमें से अधिकतर यानी करीब 70 फीसदी महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रिक परिवहन पर सरकार के जोर देने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि से भी लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख किया है। राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्य अब डीजल वाहनों पर रोक के साथ सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर दे रहे हैं। मगर, इलेक्ट्रिक

टांचे का विस्तार होता है और लीथियम बैटरी से चलने वाली रिक्शा की कीमतें और प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं तो उनकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ने की संभावना है। सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम2) योजना के तहत बैटरी के आकार के आधार पर लीथियम बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर 32,200 से 1,11,505 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। विभिन्न तीन पहिया वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के 10,000 करोड़ रुपये के परिष्वय में से कुल 987 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

अमूमन तीन पहिया वाहन चालक निम्न आय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं इसलिए वे लेड-एसिड वाले वाहनों का विकल्प चुनते हैं। इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपये होती है और 4 लाख रुपये तक जाती है। कुल लागत का करीब 40 फीसदी हिस्सा बैटरी का होता है

और लीथियम बैटरियों की तुलना में लेड एसिड बैटरियां 20 से 40 फीसदी तक सस्ती होती हैं। वाहन उद्योग के जानकारों के मुताबिक, लागत प्रतिस्पर्धा और आर्थिक लाभ से इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की पैठ और अधिक बढ़ेगी। ईई उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की बिक्री फर्राटा भरेगी और यह साल 2030 तक तीन पहिया श्रेणी में नैति आयोग के 80 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी तैयार है।

इस बीच, डीजल-पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधन वाले वाहन अपनी पकड़ खो रहे हैं। डीजल से चलने वाले तीन पहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2019 के 3,19,010 इकाइयों से घटकर फिलहाल मात्र 1,10,845 रह गई है। यह 65 फीसदी की भारी गिरावट है। इसी अवधि के दौरान पेट्रोल से चलने वाले तीन पहिया वाहनों की बिक्री भी 23,713 से घटकर 12,116 इकाइयों तक रह गई।

**बैंक ऑफ़ बड़ोदा**  
Bank of Baroda  
www.bankofbaroda.in  
निविदा सूचना  
बैंक ऑफ़ बड़ोदा नियंत्रण-2 स्टोरेज ऐप और एफडीओ टू एलसी केबल की आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।  
विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) के निविदा खंड और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।  
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देखें लें।  
प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 मार्च, 2024 है।  
स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07.03.2024  
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)  
14423-24

**बैंक ऑफ़ बड़ोदा**  
Bank of Baroda  
www.bankofbaroda.in  
सुविधा प्रबंधन विभाग  
बड़ोदा सन टॉवर, मुंबई  
निविदा सूचना  
बैंक ऑफ़ बड़ोदा अपने आवासीय सह वाणिज्यिक भवन, सिंग ए तथा भी, देना भवन, पटेल एस्टेट, जोगेश्वरी (पश्चिम) मुंबई में 4 लिफ्टों की व्यापक एएमसी सहित आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है।  
विवरण बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर निविदा खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।  
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को केवल बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर निविदा खंड में अधिसूचित किया जाएगा। बोलीकर्ता कृपया आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देखें लें।  
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 मार्च, 2024 को 15.00 बजे तक है।  
स्थान: मुंबई  
दिनांक: 07/03/2024 (एफएम, सीओए, सुरक्षा, पीडी और आरडीपी)  
महाप्रबंधक  
14423-24